साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MPHIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 18 | अंक 08 | प्रति सोमवार, इंदौर, 23 सितंबर से 29 सितंबर 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

चीन दुनिया का घोर नीच, अविश्वसनीय, डकैत देश

विश्व के देश व जनता समझे सस्ते माल का चीनी षड्यंत्र

पूरे विश्व में सभी प्रकार के घातक चीनी माल की आपूर्ति को बंद करो अन्यथा कभी भी कहीं भी हो सकता है विस्फोट

लेबनान और गाजा में हाल ही में फटे पेजर वॉकी-टॉकी से छपे समाचारों के अनुसार 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 5000 से ज्यादा घायल हुए। जो ताइवान सेआयात किए गए थे। यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह सारा कांड इजरायली जासूसी संस्था बड़ी कुशलता के साथ मोसाद ने किया। बेशक मोसाद ने इसके बारे में कहीं कोई टिप्पणी या स्वीकारोक्ति नहीं दी।

कुछ भी हो लैबनान में फटे पेजर और वॉकी टॉकी ने हीं यह तो सिद्ध कर दिया, की यथार्थ में आपके हाथ में रख मोबाइल भी पूरे बम है वह कभी भी चाहे जहां किसी भी समय विस्फोट से किसी के साथ उसके आजू- बाजू के लोगों और संपत्ति को भी उड़ा सकते हैं। इसके पूर्व में भी भारत में अनेकों चीनी मोबाइल मध्य प्रदेश में ही फट चुके हैं उससे उपयोगकर्ता व बच्चे जब में रखा होने बातचीत करते समय और चार्जिंग पर लगाने के बाद विस्फोट होने से घायल हो चुके हैं।

वैसे भी चीन के द्वारा बनाए हुए सारे मोबाइल लैपटॉप स्मार्ट टीवी आदि सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। चीन के आईटी अधिनियम 2002 की धारा 6 और 7 के अंतर्गत सारी चीज कंपनियों को चाहे वह देश में व्यापार करें या देश के बाहर उत्पादन और व्यापार करें सारी जानकारी एकत्रित करके चीन केडाटा सेंटर को भेजती रहती हैं यह बात पूरे विश्व को मालूम है और अमेरिका ब्रिटेन आदि उसके सस्ते मोबाइलों मोबाइलों के उपकरण बैटरी वह सभी प्रकार के संचार प्रणाली के उपकरणों से पूरी दुनिया की जासूसी कर रहा है। इस बात से सभी हरण परेशान तो है पर उसके माल के सस्ते होने के कारण इसका उत्पादन और बिक्री अपने देश में रोक नहीं पा रहे हैं। जबकि चीनी जासूसी से अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैरान परेशान है और जहां तक भारत का सवाल है तो यहां तो प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जैसा घोर लालची मूढ़ और मक्कार बैठा हुआ है। उसे तो कमीशन के टुकड़े डाल दो और आपको क्या चाहिए है सब ले जाओ। इसलिए मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा वह तो

उल्टे ही चीन को भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा आँखमीच के स्वयं सौंपने पर तुला हुआ है।

सभी चीन में बने, चीनी कं. द्वारा बनाए सारे मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कारें मोटर साइकल्स बैटरीज खिलौने सभी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स सभी प्रकार की वायर और केवल में लेबनान के पेजर की तरह विस्फोट हो सकता है। पर भारत में इसकी बारीकी से खोजबीन जांच परख आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब भी चाहेगा चीन न केवल आम आदमी बल्कि जल थल नभ के सैन्य अधिकारियों से लेकर कर्मियों तक कभी भी किसी को भी कहीं पर भी उड़ा सकता है। इसलिए वह बेवकूफ भारत की सीमाओं में घुसकर न केवल अतिक्रमण कर रहा है बल्कि भारत की भूमि पर अपनी सड़के रेलवे लाइन कॉलोनी गांव औद्योगिक क्षेत्र वरन बांध नहरें हवाई अड्डे हेलीपैड बनाकर शान से कब्जा कर रहा है। क्योंकि वह जानता है कि उसके सारे मोबाइल जो भारत में जो उसके सैन्य अधिकारी कर्मचारी उपयोग करते हैं उनकी सबकी उनसे लोकेशन से लेकर बातचीत इरादे मंसूबे तक सबके रिकॉर्डिंग रखता है।

बेशक उसके सस्ते माल जो अत्यधिक घातक विषैली वस्तुओं से बनाए जाते हैं। यहां तक की बच्चों को खिलौने में वह लेड ऑक्साइड जैसे घातक तत्वों का उपयोग करता है जिनको बच्चे मुंह में रख लेते हैं और उससे कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है बीमार होना तो बहुत सामान्य सी बात है पर माता-पिता और लोग समझ नहीं पाते भारत सरकार जानने के बाद में भी इस पर आज तक रोक नहीं लगा पाई बेशक यह हाल भारत का ही नहीं वरण एशिया और यूरोप के देशों में चीन के हर प्रकार के सस्ते माल की तबाही से यूरोप के अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी रूस ऑस्ट्रेलिया कनाडा से लेकर चेकोस्लोवाकिया पनामा स्पेन पोलैंड जैसे छोटे-छोटे देश भी उसके सस्ते माल के कारण उनके देश के उद्योगों को चौपट होने से लोगों की बेरोजगारी से 30 सालों से वहां की सरकारों से लेकर आम लोग भी परेशान हैं। जबकि चीनी माल के विरुद्ध पिछले 20 सालों से में लगातार लिख रहा हूं कि वह हर स्तर परन केवल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक वर्णन सरकारों के लिए भीवह घटक खेल खेल रहा है उसके बाल का आयात करना बंद करना चाहिए। और हाल ही में लेवनान गाजा में घाटी पेजर वॉकी टॉकी की घटनाओं में सिद्ध कर दिया जितना भी जल्दी हो पूरी दुनिया के हर देश को चीन में बने हर प्रकार के न केवल इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप मोबाइल बच्चों के खिलौने गाड़ियां कारें मोटरसाइकिल आदि के इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल स्टेशनरी से लेकर वस्त्र दवाई आदि सभी प्रकार के माल का पूरी दुनिया में बहिष्कार किया जाना चाहिए अन्यथा किसी भी दिन किसी के साथ अनेकों की मौत का कारण बनकर देश में कहीं पर भी कभी भी तबाही मचा सकता है। जो माल चीन में या यूरोपीय कंपनियों द्वारा बनाया हुआ है या चीनी कंपनियों द्वारा अन्य देशों में बनाया गया है। सबका बहिष्कार पूरी दुनिया में हर स्तर पर किया जाना चाहिए। उसे न केवल अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगा विदेशी मुद्रा बच्चों की अपने आप पुनः उद्योगों को जागृत करने से लोगों को रोजगार मिलेगा युवाओं को नया आत्मविश्वास मिलने से देश का भविष्य सुधरेगा।

(शेष पेज 6 पर)

भाजपा के पत्रकारों व जनता के सोशल मीडिया को जांचने के षड्यंत्रों का कानून खारिज

सत्ताधीश भ्रष्टाचार कुकर्मों अपराधों की खबरें रोकने लाये थे फैक्ट चेक बिल

फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर केंद्र सरकार की निगरानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिला झटका, प्रस्ताव खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2023 को रद्द कर दिया है. इसमें केंद्र को सोशल मीडिया मीडिया पर सरकार और उसके प्रतिष्ठानों के बारे में फर्जी, झूठी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिए तथ्य जांच इकाई (एफसीयू) स्थापित करने का अधिकार दिया गया था. न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ द्वारा 31 जनवरी, 2024 को विभाजित फैसला सुनाए जाने के बाद 'टाई-ब्रेकर न्यायाधीश', न्यायमूर्ति अतुल शरच्चंद्र चंदुरकर ने शुक्रवार को फैसला सुनाया अंग्रेजी अखबार द हिंदू की वेबसाइट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति चंदुरकर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 19 (1) (जी) (पेशे की स्वतंत्रता और अधिकार) का उल्लंघन करता है. उन्होंने कहा कि नियमों में नकली, झूठा और भ्रामक शब्द किसी परिभाषा के अभाव में अस्पष्ट और इसलिए गलत है. न्यायाधीश ने कहा, आलोचना नियम के परिणामस्वरूप मध्यस्थ के रूप में भयावह प्रभाव पड़ता है

कब लाया गया कानून?

अप्रैल 2023 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MEITY) ने आईटी नियम, 2021 में संशोधन करके एफसीयू की स्थापना की. इसके बाद, राजनीतिक व्यंग्यकार और स्टैंड-अप कलाकार कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैगजीन (एआईएम) ने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के माध्यम से आईटी संशोधन नियम, 2023 के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उन्हें

मनमाना, भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला और अस्पष्ट कहा गया.

मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत एफसीयू की स्थापना संबंधी सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा दी. इसके बाद जुलाई 2024 में एफसीयू का बचाव करते हुए केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एफसीयू लोगों को गलत सूचना फैलाने से रोकेगा. मेहता ने कहा, यह दृष्टिकोण फर्जी, झूठी और भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए सबसे कम प्रतिबंधात्मक तरीका है. निजि कंपनियां और व्यक्ति भी तथ्य जांच इकाइयां बनाए रखते हैं और सरकार भी जनता को सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए इसी तरह न्यायसंगत है.कई मामलों में, सरकार निर्णायक और लाभार्थी के रूप में कार्य करती है, जैसे की भूमि विवादों में. (शेष पेज 2 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

चुनाव से पूर्व हटाने, चुनाव के समय बचाने की वाचालता

वर्तमान सत्ताधीशों जिसमें मोदी अमित शाह बीडी शर्मा के पिछले 10 सालों से चुनाव पूर्व के भाषण सत्ता हथियाने के बाद के भाषण आरक्षण विरोधी व सामाजिक न्याय की सबसे बडी शत्रू भाजपा के बिछाए जाल से बचना ही होगा। संघ व भाजपा का एकमात्र एजेण्डा रहा हैं कि देश में ऐसा हिन्दू राष्ट्र बने जिसके चलते समूचे राष्ट्र की सफिर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उन्हें अपनी कहानी बातों को विपक्ष में दौड़ना शुरू किया तो उन्होंने उल्टे ही विपक्ष पर आरोप लगाकर अपने भाषण से पलटी मार गए। सत्ता व मिल्कियत मुट्ठी भर उच्च व श्रेष्ठतम हिन्दू जातियों के हाथों में क़ैद रहे, शेष पूरा देश दोयम दर्जे का संत्रापी अन्याय व अपमान भुगतता रहे और देश में निम्न, छोटी व शोषित जातियाँ को न कोई विशेष अवसर मिले न लाभ मिले न सामाजिक विशेष संरक्षण मिले और न उन्हें सत्ता के अधिकार मिले, उसी तरह मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध व पारसीयों को अल्पसंख्यक का संवैधानिक अधिकार क़तई न मिले याने देश में किसी प्रकार का कोई आरक्षण छोटी व निम्न जातियों व वर्गों को किसी क़ीमत पर न मिले न किसी को अल्पसंख्यक का भी दर्जा व संरक्षण मिले. इसीलिए संघ व भाजपा के पुरखे जनसंघ ने तो देश के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया और सत्ता हासिल कर डा. अम्बेडकर का संविधान कुचल दलितों व पिछड़ों के आरक्षण का हर हाल में खात्मा ही उनका सबसे बड़ा ध्येय व सपना था और इसी स्वप्न को साकार बनाने हेतु मोदी के नेतृत्व में चार सौ पार कर नया संविधान लाकर सारे तरह के आरक्षणों व संवैधानिक संरक्षणों को दफ़न कर देने की उनकी षड्यन्त्रकारी मंशा को देश के दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों ने नेस्तनाबूत कर मोदी व भाजपा को इस विषमता के विकटतम हालातों में पहुँचा दिया कि उनको मुस्लिम समर्थक चार चार दलों के चरणों में घुटने टेकर नाक रगड़ते इतिहास की सबसे बड़ी विपरीत विसंगतियों से भरी बेमैल किन्तु कभी भी ढह जाने वाली दूसरों की रहमत व दया पर मिलीजुली सरकार बनाने को मरखप के मजबूर होना पड़ा हैं.हालत इतने दयनीय व विषमयकारी हो गये हैं कि एक एक राज्य में अपनी दिखती हार को बचाने के लिए आरक्षण को खत्म कर उसका हर हाल में खात्मा करने वाली भाजपा को अपने कदमों पर पीछे भागते-दौड़ते घुटने टेक मजबूरी में आरक्षण के पक्ष में ढोल बजाने के भारी भरकम शातिरता से भरे स्वाँग रचने व बहुरूपियेपन के तिकड़म पर टिकना पड़ रहा हैं.मगर जानकारों का कहना कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा की इस धोखाधड़ी से भरी नियोजित छद्म नौटंकी की चाल में अब दलित, अतिदलित, आदिवासी व पिछड़ा, अतिपिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग न तो फँसेगा न उनके छिपे षड्यंत्र को कामयाब होने देगा क्योंकि पिछड़ों को आरक्षण देने पर वी पी सिंह की सरकार को भाजपा ने जिस तरह धराशाही कर इस आरक्षण के ऐतिहासिक न्याय को कुचलकर रोंधने वाले करतूत व कुकृत्य किए और मण्डल को नेस्तनाबूत करने के लिए कमण्डल का सहारा लेकर पिछड़ों के सामाजिक न्याय को तबाह करने वाली भाजपा कितना भी गिरगिटी रंग बदले, झूठ का जाल फैंके, मोदीजी अपने भाषणों में कितना भी ऊँचे व लम्बे जुगाली के जज्बाती शगूफ़े खडे करे मगर सामाजिक न्याय के करोड़ों करोड़ लोगों को ऐसे राजनीतिक धोखेबाज़ों से बेहद सावधान, सतर्क व बचकर ही रहना होगा। मुट्ठी भर ऊँच जातियों का राज देश की छाती पर लादते थोपने वालों की जीत हमेशा सामाजिक न्याय की हार,आरक्षण के संवैधानिक अधिकारों की मौत और डा. अम्बेडकर के सपनों की मृत्यु व उन्हीं के महानतम पराक्रम व पुरुषार्थ की हार होगी.

तिरुपति के लड्डू प्रसाद में घी की अपेक्षा मछली का तेल..सूअर, गाय की चर्बी कांड

हिंदुओं व आस्थाओं को खत्म करने तुली आरएसएस और भाजपा

प्रदेशों कि दुग्ध सहकारी सांडों को हड़पने और खत्म करने का षड्यंत्र

दक्षिण के जाने माने तिरुपति मंदिर में बनने वाले प्रसाद में हाल ही में मछली सूअर व गाय की चर्बी का भारी कांड सामने आया। बेशक इसके पीछे भी भाजपा का ही पूरा षड्यंत्र है।

चलिए इस दुखद कथा के पीछे कौन सी पटकथा शामिल है.. और उस पटकथा का एक हिस्सा मध्य प्रदेश भी है... कैसे..?? तो आइए उसे समझते हैं.. कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं..निष्कर्ष आप निकाल लीजिएगा..।

तो पहला तथ्य.. कभी इंदिरा गांधी के जमाने में शुरू हुए ऑपरेशन श्वेत क्रांति की पैदाइश थे, देश भर के सांची ,अमूल जैसे दूध संघ.. इसमें सबसे प्रतिष्ठित दूध संघों में से एक रोजाना 80 लाख लीटर दूध एकत्र करने वाला कर्नाटक दूध संघ (KMF) का ब्रांड नंदिनी भी शामिल है..

दूसरा तथ्य दिमाग में रखिए ..बड़ी कंपनियों की नजर काफी समय से , डेयरी क्षेत्र के अरबों के कारोबार को दुहने पर है.. केंद्र की मोदी सरकार प्रयासरत है कि देशभर के सांची, नंदिनी जैसे स्थापित ब्रांड वाले सहकारी दूध संघ, केंद्र के अधीन आ जाएं.. उनका संचालन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पास आ जाए। इसके पीछे तर्क... दावा वही 'तपस्या में कोई कमी रह गई होगी' वाले 3 किसान बिल जैसा , यानी किसान हित का था..

अब जरा कर्नाटक की एक पुरानी घटना याद दिलाता हूं..यूं तो 6-7 सालों से दूध संघों को पहले बदहाल करो और फिर हथियाने की रणनीति के तहत.. समय-समय पर हमले होते रहे हैं.. ऐसी ही हड़पने की अप्रत्यक्ष कोशिश कर्नाटक के नंदिनी ब्रांड के साथ भी की गई... लेकिन कर्नाटक की जनता का इस ब्रांड से जुड़ाव और भरोसा कितना होगा कि, इसकी भनक लगते ही जनता, स्थानीय राजनीतिक दल विरोध में आ गए.. यहां तक की नंदिनी यह चुनावी मुद्दा बन गया.. केंद्र की मोदी सरकार को कदम वापस खींचने पड़े।

अब आते हैं चौथे तथ्य पर ..तिरुमाला देवस्थान में बनने वाले लड्डू प्रसादम के लिए घी सप्लाई करने की जिम्मेदारी 40-50 सालों से सहकारिता क्षेत्र के कर्नाटक के नंदिनी घी के पास थी। तिरुपति में सालाना करीब 4.5 हजार मी. टन की की जरूरत होती है। यानी नंदिनी घी का एक बड़ा स्थाई ग्राहक।

नंदीनी को हड़पने की कोशिश कर्नाटक की जनता और नेताओं ने असफल कर दी.. चोर दरवाजे से अमूल को घुसाने की कोशिश असफल हो गई। जाहिर है यह बात मोदी सरकार को नागवार गुजरी। नजरे टेढ़ी हुई। 40-50 सालों से तिरुपति को रियायती दामों पर घी सप्लाई कर रहे कर्नाटक दूध संघ के हाथ से ,घी सप्लाई का ठेका निकाल कर निजी हाथों में पहुंचा दिया गया। दरअसल जब दूध की कीमत बढ़ी तो घी की कीमत भी बढ़ी.. नंदिनी घी के भाव भी बढ़े.. लेकिन सिर्फ लड्डू बेचकर 500 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले तिरुमाला देवस्थान ने, दो चार रुपए के पीछे घी सप्लाई का ठेका, निजी हाथों में दे दिया। तब भी कर्नाटक दूध संघ के अध्यक्ष ने आगाह किया था कि दूध के जो भाव है उसे देखते हुए, इतने कम भावों पर घी बनाना और बेचना संभव ही नहीं है.. यदि कोई देता है तो यह गुणवत्ता से समझौता करना होगा.. (ऐसी तमाम पुरानी मीडिया रिपोर्ट यूट्यूब पर मौजूद हैं).. खैर सनातन के इन फर्जी रखवालो को गुणवत्ता से क्या लेना देना..?? नंदिनी से हजारों टन घी का ठेका छीनकर हुकुम उदूली का सबक तो सिखा दिया ना..!!

अब आईए समझते हैं तिरुमाला देवस्थान के चर्बी वाले लड्डू , नंदिनी घी और इस घटना का प्रदेश से क्या रिश्ता है..?? सांची हमारा जाना पहचाना नाम है.. पीढियां सांची दूध पीकर बड़ी हुई है..। प्रदेश में सांची के 11000 गांव में फैली 33000 दूध समितियां के नेटवर्क को हथियाने कोशिश तो शिवराज के जमाने से ही होने लगी थी। शायद वे असली खेल को समझते थे.. इसलिए केंद्र का खेल पूरी तरह सफल नहीं हो पाया.. लेकिन इसकी पूर्णाहुति, मौजूदा सरकार के कुछ दिन पहले लिए गए निर्णय से हो चुकी है.. अभी तो किसान हित की आड़ में सांची की कमान नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पास पहुंचने का रास्ता साफ हुआ है.. फिर यह कमान धीरे से किन हाथों मे पहुंचेगी..?? इस को समाजशास्त्रीय राजनीति शास्त्र नहीं, बल्कि अपराध शास्त्र के नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए.. पूरा असली खेल समझ में आ जाएगा।

सांची को हड़पने की शुरुआत हो चुकी है ...लेकिन यह कर्नाटक की नहीं ,मध्य प्रदेश की जनता है.. वह तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए 'हिंदू खतरे में है' वाले मैसेज पढ़ने फॉरवर्ड करने.. हनुमान आरती बाबाओ के दरबार में हाजिरी लगाने.. 5 किलो राशन, लाडली बहना मे मगन है.. रही बात विपक्षी दलों के नेताओं की तो, उनके पास ना तो इस षड्यंत्र को समझने की समझ है और ना ही साहस..हां जिस ईमानदार अधिकारी प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने समझा, उसे इस 'केंद्र शासित प्रदेश' ने रातों-रात बाहर का रास्ता दिखा दिया.. लूट पर मोहर लग चुकी है। तो हे व्हाट्सएपिया सनातनी ..!! यदि तुमने भी पिछले साल 2 सालों में तिरुपति का प्रसाद खाया है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है... किसी पंडित से संपर्क करो.. हमारे धर्म में प्रायश्चित पूजा पाठ का विधान है.. वह तुम्हारा सनातन सुरक्षित कर देगा.. बस फिर क्या नए जोर से से जुट जाना अपने राष्ट्रीय कर्तव्य में.. भूल गए..?? अरे वही काम.. हिंदू खतरे में जो है..

सत्ताधीश भ्रष्टाचार कुकर्मों अपराधों की खबरें रोकने लाये थे फैक्ट चेक बिल

पेज 1 का शेष

हालांकि, इस संदर्भ में, मैं निर्णायक के रूप में कार्य नहीं करता हूं. मेरी (सरकार की) भूमिका केवल झूठ या गलत सूचना के उदाहरणों की पहचान करना और उन्हें उजागर करना है.

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ एडवोकेट नवरोज सीरवाई ने फरवरी 2024 में संशोधित नियमों के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले कई बिंदुओं पर जोर दिया. प्रेस सूचना ब्यूरो पहले से ही एक सरकारी संगठन है, जो सरकार के व्यवसाय के बारे में ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करता है, जिन्हें वह नकली, गलत या भ्रामक मानता है. विभाजित निर्णय के बाद से संघ द्वारा एक भी मामला नहीं बताया गया है, जिसमें एफसीयू की अनुपस्थिति ने उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा किया हो. यह इस बात का एक मजबूत मामला है कि अंतरिम राहत क्यों दी जानी चाहिए नए आईटी नियमों (2023) के अनुसार, सरकार फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एफसीयू की मदद से केंद्र सरकार के व्यवसाय से संबंधित किसी भी सामग्री/ समाचार को हटाने के लिए कह सकती है, जिसे फर्जी, झूठा या भ्रामक के रूप में पहचाना गया हो. सरकार द्वारा नियुक्त एक संगठन ऐसी सामग्री का मध्यस्थ होगा, और यदि मध्यस्थ संगठन के निर्णय का पालन नहीं करते हैं, तो वे आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत दोषी माने जा सकते हैं.

इस फैसले का डिजिटल अधिकार समूहों ने स्वागत किया, जिन्होंने तथ्य जांच इकाई की शुरूआत की तीखी आलोचना की थी और इसे सरकार द्वारा किया गया अतिक्रमण बताया था. दिल्ली स्थित सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की संस्थापक मिशी चौधरी ने एक बयान में कहा, 'सरकारों को कभी भी तथ्य जांच के व्यवसाय में नहीं आना चाहिए क्योंकि यह स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज का काम है.'

कॉमेडियन कुणाल कामरा, जिन्होंने एआईएम और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के साथ एफसीयू को चुनौती दी थी, ने कहा- 'वे कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हम भारत के लोग हमेशा संविधान की रक्षा करेंगे ताकि सत्ता के नशे में चूर लोगों को नमन किया जा सके, संविधान की प्रस्तावना की एक छवि के साथ.' इस फैसले के बाद कुणाल कामरा को टैग करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा है- 'शुक्रिया, कुणाल कामरा लोगों की हंसी बंद होने से बचाने के लिए। अपने पेशे को दांव पर लगा कर आपने कितने खतरे उठाए. सबके लिए यह लड़ाई लड़ी. आपके वकील एर्नि्न का भी शुक्रिया। IT नियमों संशोधन असंवैधानिक माना गया है. इसके लिए आप सभी कुणाल कामरा को बधाई दे सकते हैं. चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक माना गया. चुनाव के बाद बिना दोष साबित हुए किसी के घर पर बुलडोज़र चला देना भी असंवैधानिक माना गया. असंवैधानिक कार्यों की पूरी सूची बन सकती है.'

भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारियों का अहंकार पूरा हो

कानून रखैल, अधिकारी, कर्मचारी भेड़, बकरी जनता कीड़े मकोड़े, देश जाए भाड़ में

वाणिज्य करायुक्त के 18 अधिकारियों को 3 दिन के पावर देते ही माफिया को खबर। सी व एस जीएसटी को ट्रकों के दिये नंबर, क्षेत्र पर कोई कार्यवाही किसी ने नहीं की।

भारत की सत्ता को केंद्र से लेकर राज्यों तक पूरा भारतीय प्रशासनिक बनाम प्रताड़ना सेवा अधिकारी चलाते हैं। जो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर 6 लाख से ज्यादा गांवों तक की शासकीय व्यवस्थाओं को प्रशासनिक स्तर पर वैधानिक रूप से चलाने के लिए आइएएस बनाम (अपने आप को आईएमसेफ कहते थे) इतिहास और वर्तमान की व्यवस्था की व्याख्या के अनुसार भारतीय प्रताणना सेवा अधिकारी जिनके लिए देश का संविधान और कानून उनकी रखैल चुने हुए सांसद व संसद के प्रधानमंत्री, राज्यों के विधायक मुख्यमंत्री मंत्री सब शतरंज की विसात पर बैठे राजा वजीर ऊंट घोड़े हाथी पैदल उनके हाथों के नीचे नाचने वाले मोहरे विभागों के अधिकारी कर्मचारी इंजीनियर डॉक्टर वैज्ञानिक सब भेड़ बकरियां और कुछ खास अपने फायदे के काम करवाने वाले देसी विदेशी पूंजीपति बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारी उनके धन सुख सुविधा सुरा सुंदरी उपलब्ध करवाने वाले दलालों से ज्यादा कुछ नहीं होते। स्वाभाविक है उनका अहंकार ज़िद्द अड़ियल पन पूरा करने वे वास्तविक सत्ता के बेताज बादशाह सारे छल कपट जालसाजी चालबाजी करते हैं। उनकी बला से देश और देश की संपत्तियां संस्थान जनता के हितों की रक्षा और साधने की अपेक्षा उनका अपना हित साधन सर्वोच्च होता है। देश जाए भाड़ में। कल का बर्बाद होता हो तो आज बर्बाद हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 25 साल में देखने में आया की यह प्रशासनिक बनाम प्रताड़ना अधिकारी घोर भ्रष्ट जालसाज डकैत होने के साथ राजनीतिक और आपराधिक माफिया को पालने संरक्षण देने अपने हितों को साधने में निष्ठुर हुआ है। पिछले तीन लोकसभा चुनावों में आपने देखा किस प्रकार से न केवल जिले का कलेक्टर एसडीएम एडीएम से लेकर जितने भी पर्यवेक्षक आते हैं सभी सारे हरामखोर आईएएस अधिकारी ही होते हैं। के साथ सचिव प्रधान मुख्य सचिव व देश व राज्यों के सभी चुनाव सहायक उपायुक्त आयुक्तों जगदीश में किस प्रकार से भयानक जालसाजी का कांड किया। पूरे देश में लोकसभा चुनाव में इन जलसा डकैत हरामखोरों ने फर्जी संचार माध्यमों से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जलसाजी के साथ पूरे देश में कहीं पर भी मशीनों से प्राप्त मतों की सूची के बाद हर कक्ष की, कक्षों के बाद सभी कक्षों के हर चक्र की, हर चक्र की वर्गीकृत सारणी के बाद सभी चक्रों की वर्गीकृत सारणीया एक्सेल शीट ही नहीं बनाई और मनमानी तरीके से अपराधिक प्रवृत्ति के बलात्कारी, डकैत, जालसाज, लुटेरे, सत्ताधीशों के सामने अपने मोटे लाभ, डर और श्रेष्ठता को स्थापित करने सिर झुकाकर उनके अनुसार परिणाम दिए जहां अन्य उम्मीदवार दमदार और जांबाज थे उन्होंने डरा धमका कर अपने हिसाब से परिणाम लिए परंतु पूरे देश में देश की व जनता की बर्बादी और उसके खिलाफ होने के बावजूद भी पुनः तीसरी बार देश की पूरी तरह से बर्बादी के लिए जिता करो सत्ता में बैठा दिया।

यथार्थ में पूरे देश मेंयह भारतीय प्रधान सेवा अधिकारी सभी प्रकार के भू कॉलोनी खनन रेत शराब परिवहन ड्रग करचोर स्कूली, उच्च, तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा सहकारिता ठेका आदि सैकड़ों प्रकार के माफियाओं को पाल कर मोटी वसूली करता है आपने देखा, किस प्रकार से भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों पर छापे मारने के बाद करोड़ों रुपए का नगदी आभूषण सोना चांदी मिलने के साथ ही सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां शेयर्स ऋणपत्रों अनेकों बैंकों की सावधि जमायें, सैकड़ो करोड़ के अनेकों उद्योगों कालोनियों भवनों में निवेशआदि मिलते हैं।

पिछले समय माया के तीन समाचार पत्रों में वाणिज्य कर में लोहे से बिना कर चुकाये ट्रकों के सचित्र विवरण प्रकाशित किए थे। प्रशासन के बाद चुकी समाचार पत्र भोपाल में मुख्यलयों में बांटा जाता है। शायद शर्मा शर्मी और हल्ला मचने के कारण में प्रदेश के 18 वाणिज्य कर अधिकारियों को धारा 68, 71 के अधिकार दिए. जिसकी खबर सबसे पहले कर चोर माफिया के पास पहुंची। उसके सूत्रों से ही मालूम पड़ा की वाणिज्यकर आयुक्त ने प्रदेश में इंदौर के अंकेक्षण विभाग के कर अधिकारी परमार को, व्रत क्र. 2 के एमएस चौहान को झाबुआ के राठौर को सतना ग्वालियर वह अन्य वृत्तों के अधिकारियों को कर चोरी रोकने माल भागों को पकड़ने के अधिकार दिया है। जिसमें से अधिकांश ने इसके पहलेइससे संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की थी इसलिए उनको कुछ समझ में ही नहीं आयाऔर सार्थक परिणाम जो मिलनी चाहिए थे वह नहीं मिले। अपने अहंकार को पूरा करने करायुक्त धनराजू ने अपने ही विभाग में कार्यरत इस कार्य की विशेषज्ञ प्रदेश की 6 एंटी इवेजन विंग को किसी प्रकार की कोई अधिकार नहीं दिए। जो ट्रकों के नंबर विवरण के साथ दिए गए जो उन पर कार्रवाई करने के लिए झाबुआ और इंदौर थे क्षमता प्राप्त अधिकारियों को संदेश भेज कर कार्य करने के लिए कहा गया। तो इंदौर .व्रत दो के अधिकारी एमएस चौहान ने फोन ही नहीं उठाया। बेशक नंबर आयुक्त धनराजू के साथ अपर आयुक्त श्रीमती रजनी सिंह को भी भेजे गए थे। वर्ल्ड ट्रक राजगढ़ में खाली होकर आसानी से निकल गया और अन्य ट्रकजो मध्य प्रदेश में घुसने वाले थे पावर खत्म होने के बाद प्रदेश में घुसे और खाली होकर माल लेकर निकल गएपर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की जब सूचना के अधिकार में इसकी जानकारी मांगी जाती है तो 2009 के राज्यपाल के सूचना के अधिकार में जानकारी देने के आदेश की प्रतिलिपि

का हमारा अधिकार जानकारी नहीं दी जाती।

अगले माह अक्टूबर में दिवाली और दशहरे जैसे दो महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति के त्यौहार होने के कारणबाजारों में जमकर उपभोक्ता खरीदी करेंगे। जिसमें दुकानदार उपभोक्ताओं से सभी प्रकार का सीजीएसटी और एसजीएसटी हर माल पर वसूलेंगे। जिसमें वस्त्रों आभूषणों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रिज एसी मोबाइल टीवी आदि से लेकर पटाखे तक का सैकड़ों करोड़ का कर चोरी कर माल पूरे प्रदेश में बेंचा जाएगा। परंतु सरकार को केवल अक्टूबर महीने में लगभग 2000 करोड रुपए की अधिकारियों को धारा 68 और 71 के अधिकार न देने से हानि हो जाएगी। बेशक एंटी इवेजन विंग पर काफी आरोप लगाते हैं। यह बात सही है। पर आरोपों के इतर शासन के करूं की चोरी करवाने की खुली छूट देकर माफियाओं को छुट्टा छोड़ देना कहां तक उचित होगा?

जबकि सचिया है की सरकार अपने अधिकारियों को राजस्व वसूली के अधिकार न देकर राजस्व की हजारों करोड़ की हानि तो करवाता ही है। और उसका सीधा लाभ जनता को मिलने की अपेक्षा उल्टे ही 12 से 28% की धर्म से जनता को लुटवाता अवश्य है। दूसरी तरफ प्रदेश में दूसरी बार मध्य प्रदेश की सरकार राजस्व आए ना होने के आधार पर पुनः 5000 करोड़ का कर्ज ले रही है जबकि पूर्व से ही चार लाख करोड रुपए से ज्यादा का कर्ज प्रदेश सरकार पर है और उसके 1% की ब्याज दर भी मानी जाए तो लगभग प्रति माह 4000 करोड रुपए केवल ब्याज में चले जाते हैं। यही हाल खनन में 60% राजस्व की, शराब में 50% की, परिवहन करों में 40% चोरी होती है। पंजीयन में 20 से 30% की चोरी की अतिरिक्त अधिकांश राजस्व वसूली के विभागों में चोरी होने के साथ अधिकांश खर्च करने विभाग वाले विभागों मेंभी यह आंकड़ा बढ़कर सड़क छत्रपति शतक पहुंच गया है जो प्रदेश की जनता की सिर पर कर्ज लाद रहा है। कर्ज लेना यह सिद्ध करता है कि प्रदेश के प्रशासनिक बनाम प्रताड़ना सेवा अधिकारी केवल अपने हितों के साधन में लगे हुए हैं और प्रदेश को वित्तीय कष्टों में डुबाने में लगे हैं।

Mh18 bg 8569 ... 1
Mp09 hh 0781 ... 2
Mp 46 h 7772 ...3
Mh18 bh 5463 ...4
Mh18 bg 1015 ...5
Mp 11 h 0603 ...6
Mh18 bg 7136 ... 7
Mh18 bg 0375 ... 8
Mh18 ba 8318 ... 9
Mp09 hh 9986 ...10
Mp 12 h 0362 ...11
Mh18 bz 6650 ...12
Mp09 hg 7970 ...13
Mp09 hh 5536 ...14
Mh18 ba 1639 ...15
Mp 46 h 0499 ... 16
Mp09 hg 6594 ... 17
Rj09 gb 8833 ... 18
Mp09 hh 2175 ... 19
Rj09 gg 6090 ... 20
Mh18 ba 9781 ... 21
Mh18 bg 3981 ... 22
Mp09 hh 3799 ... 23
Mh18 bz 3731 ... 24
Rj09 gb 0695 ... 25
Mh18 bg 7469 ... 26
Mh18 aa 9485 ... 27
Mh18 bh 7046 ... 28
Mh18 ba 0612 ... 29
Mh18 bg 3133 ... 30
Mh18 ba 1586 ... 31
Mp09 hh 2701 ... 32
Rj09 gc 1974 ... 33
Rj09 gb 5427 ... 34
Rj09 ga. 5353 ... 35
Rj09 gb 9670 ... 36
Mh18 ba 7786 ... 37
Mp 13 h. 0265 ... 38
Mh18 bz 1432 ... 39
Mh18 bg 3505 ...40
Mh18 bg 0814 ...41
Gj 34 t 3350 ... 42
Rj09 gd 4820 ... 43
Rj 17 gb 1820 ... 44
Rj 17 gb 1490 ... 45
Mp09 hh 4997... 46
Mp09 hh 1753 ... 47
Mh18 bz 4443 ... 48
Mh18 bz 4007 ... 49
Mh18 aa 9897 ... 50
Mp09 zq 9497 ... 51
Mh18 bz 7844 ... 52
Mh18 bz 1846 ... 53
Mh18 bz 9761 ... 54
Mh18 bz 7466 ... 55
Mp46H7772
MH43Y4683

यह गाड़ियां जालना से निकल चुकी हैं और सिरपुर घाट में खड़ी हुई है जो रात्रि में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे अलग-अलग मार्गो से

इसकी जांच करवा करआप उचित कार्रवाई कर सकते हैंजैसा कि मेरे पास वहां से जानकारी प्राप्त हुई है.

स्टेशन पर चाय बेचने वाला हड़प व बर्बाद कर रहा रेल्वे

पेज 1 का शेष

मार्च 2020 से भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन को ट्रेन किराए पर दी जाने वाली छूट भी बंद कर दी है। इस छूट के तहत महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत की छूट और पुरुष एवं ट्रांसजेंडर के लिए 40 प्रतिशत की छूट मिलती थी।

मोदी सरकार ने बच्चों के हॉफ टिकट की सुविधा को भी खत्म कर दिया है। अब ट्रेन में सफर करने वाले पैरेंट्स को अपने 5 से 12 साल के बच्चों के लिए भी फुल टिकट लेना पड़ता है। CAG की रिपोर्ट के अनुसार 'राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष' (RRSK) में 75 प्रतिशत धनराशि कम कर दी गई है। अब इस धनराशि का उपयोग रेलवे अधिकारियों के अनावश्यक खर्चों और आराम सुविधाओं पर किया जा रहा है।

भारतीय रेल से स्लीपर कोच की संख्या लगातार घटाकर गरीबों से उनकी किफायती यात्रा की सुविधा छीनी जा रही है। स्लीपर कोच की संख्या कम होने के कारण अब स्लीपर कोच की हालत जनरल कोच की तरह हो गई है। आरक्षित टिकट होने के बावजूद गरीब और मध्यमवर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस शासनकाल में 5 रुपये में मिलने वाला प्लेटफार्म टिकट अब 50 रूपये का मिलता है। रेल में अपने सगे सम्बन्धियों को लेने जाना या छोड़ने जाना अब सबके बस की बात नहीं रह गई है। रेल भाडा और माल भाडा लगातार बढाया जा रहा है और बदले में सुरक्षा, सुविधा और रियायत देने के जगह यात्रियों को मौत परोसी जा रही है। कुल मिलाकर नरेन्द्र मोदी ने भारतीय रेल को निगलने का काम किया है। अब रेल यात्रा अंतिम यात्रा सा खौफ देने लगी है। रेल मंत्री रेल दुर्घटनाओं पर संसद में कहते हैं कि ये छोटी छोटी घटनाएँ हैं। पूरी बेशर्मी से सरावोर मोदी सरकार आम जनता को परेशान करने पर तुली है।

नए साल के लिए आपने जो वायदे किये थे, उन पर आप कितना अमल कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। आप वजन कम करने के लिए डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि इसमें आप कौन- सी गलतियां कर रहें है, डाइटिंग प्लान को पूरी तरह रोकिये मत। उसमें जो गलतियां कर रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सुधार करें...

स्वास्थ्य बिगाड़ें डाइटिंग की यें गलतियां

जनवरी का महीना गुजर चुका है। नये साल के लिए आपने जो वायदे किये थे, उन पर आप कितना अमल कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा।

अपना वजन कम करने के लिए डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि इसमें आप कौन-सी गलतियां कर रहे हैं, डाइटिंग प्लान को पूरी तरह रोकिये मत। उसमें जो गलतियां कर रहे हैं, बस थोड़ा उसमें सुधार करें।

स्नैक्स में नट्स

विभिन्न अध्ययनों के अनुसार नट्स को स्नैक्स के तौर पर खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। दूसरे अन्य क्रिस्पी, तुलना में यह आपको लंबे समय तक पेट भरे होने की फीलिंग देते हैं। इनमें पौष्टिक तत्व और फायदा होता है। लेकिन इन सूखे मेवों में कैलोरीज और सेचुरेटिड फैट भी ज्यादा होता है। एक मुट्ठीभर मूंगफली में 150 कैलोरीज होती हैं। इसलिए अगर आप स्नैक्स में नट्स ले रहे हैं तो थोड़े खाएं, मुट्ठीभर मेवों से आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं।

वजन तोलें

अगर आप अपने वजन को रोज तोलते हैं और आपको लगता है

यह कम हो गया है तो किसी भ्रम में न रहें। शरीर में मौजूद पानी से भी वजन ज्यादा होता है।

डाइट प्लान

अच्छे डाइट प्लान में कभी-कभी कुछ भी खाने की छूट होनी चाहिए। यदि आप 80 प्रतिशत स्वस्थ भोजन लेते हैं तो 20 प्रतिशत इधर-उधर से कुछ खा सकते हैं। इसके लिए कभी-कभी चॉकलेट या एक गिलास वाइन ली जा सकती है।

इसलिए सप्ताह में भले ही एक बार वजन तोलें। वजन उस समय तोलें जब आप सुबह के समय टॉयलेट जाने के बाद नहाने के लिए तैयार हों और शरीर पर कपड़े न हों।

फल और सब्जियां

इस बात में कोई दो राय नहीं कि फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन इससे वजन कम नहीं होता। विभिन्न अध्ययनों के जरिये पता चलता है कि फलों में मौजूद शुगर (फ्रेक्टोज) से पेट के भरे होने जैसी संतुष्टि नहीं होती। जबकि दूसरी मीठी चीजें खाने के बाद हमें संतुष्टि मिलती है। अगर आप ज्यादा फल खाते हैं तो उनके साथ प्रोटीन के दूसरे स्रोत भी लें। इससे आपको भूख कम लगती है।

कैलोरीज पीना

अगर आप पूरा दिन कुछ खाने की बजाय चाय और कैपीचिनो कॉफी लेते हैं तो सतर्क हो जाएं।

औसतन एक कैपीचिनो में 120 कैलोरी और 8 ग्राम फैट होती है। 8 कप चाय में डाले गये दूध में भी 400 कैलोरीज होती हैं। इसलिए किसी भ्रम में न रहें। चाय और कॉफी भी वजन बढ़ाते हैं।

इनमें स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल करें या हर्बल चाय लें।

डाइट ड्रिंक्स

विभिन्न अध्ययन इस बात का खुलासा करते हैं कि डाइट ड्रिंक्स जीरो कैलोरीज ड्रिंक से बेहतर होते हैं। कृत्रिम स्वीटनर्स हमारी पाचनक्रिया पर असर डालते हैं और इससे हम असंतुष्ट रहते हैं, जिसकी वजह से डाइट ड्रिंक्स हमें ज्यादा खाने के लिए उकसाते हैं। इसके लिए पानी पीयें और फ्रूट टी लें।

सलाद की ड्रेसिंग

सलाद भी कैलोरीज से भरपूर होते हैं और इनमें फुल फैट और कैलोरीज भरपूर होती हैं।

सलाद की ड्रेसिंग भी वजन बढ़ाती है। बाजार की लाइट फ्रेंच ड्रेसिंग में प्रति टेबल स्पून 70 कैलोरीज होती हैं। घर में बनी सलाद ड्रेसिंग में ऑयल और विनेगर या लेमन जूस में भी एक बार में 100 कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं। इसलिए सलाद में साइड पर ड्रेसिंग करें और घर में ही इसे तैयार करें।

सीड्स टॉपिंग्स

कद्दू, सनफ्लावर, तिल और दूसरे सीड्स हमारी पुडिंग को क्रंची बनाते हैं। यही योगर्ट और सलाद में भी इस्तेमाल में लाये जाते हैं।

एक टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स में 93 कैलोरीज होती हैं। इसलिए, अपने सलाद में अगर आप सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसे मुट्ठीभर खुले मन से डालने की बजाय टेबल स्पून से नापकर डालें।

सर्दियों में लगाएं केले का फेस पैक

सर्दियों में त्वचा अक्सर रूखी और बेजान हो जाती है, जिससे चेहरा बदसूरत लगने लगता है। ऐसे चेहरे पर फिर चाहे आप कितना भी मेकअप कर लें या कोई भी प्रॉडक्ट लगा लें, पर खूबसूरती निखरकर नहीं आती। इसलिए जरूरी है कि स्किन को हेल्दी रखने और उसकी ड्राईनेस दूर करने के लिए महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगाने के बजाय घर पर ही तैयार फेस मास्क या पैक लगाएं।

वैसे सर्दियों में केले और मिल्क पाउडर का फेस पैक काफी सही माना जाता है। इस फेस पैक की खास बात यह है कि इसे किसी भी तरह की स्किन पर लगाया जा सकता है। इन दोनों चीजों के स्किन पर क्या फायदे हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं।

स्किन के लिए केले के फायदे

केला स्किन के लिए एक नैचुरल मॉइश्चराइजर का काम करता है। इसमें पोटेशियम, विटामिन ए और अन्य कई पोषक तत्व होते हैं जो स्किन की ड्राईनेस को दूर करते हैं और उसे स्मूद बनाते हैं। यह स्किन से एक्स्ट्रा ऑइल को निकालने में मदद करता है। इसलिए यह ऑइली स्किन के लिए भी उपयोगी है। केला स्किन के लिए एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर है जो डेड सेल्स को रिमूव करने में भी मदद करता है।

जो महिलाएं चेहरे पर केले का प्रयोग करती हैं उनकी स्किन लंबे समय तक यंग रहती है। केले में ऐंटी-ऐजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन को लंबे समय तक जवां बनाए रखती हैं।

सर्दियों में घर पर बनाएं ये मैजिक सिरम

सर्दी के मौसम में स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में ग्लिसरिन एक ऐसा प्रॉडक्ट है जो आपकी मुश्किल चुटकियों में हल कर सकती है।

दाग-धब्बे भी होंगे दूर

सर्दियों में स्किन को ग्लोइंग और दाग-धब्बे रहित रखने के लिए ग्लिसरिन, गुलाब जल और नींबू से बना होममेड सिरम बेस्ट है।

तीनों में हैं कमाल के गुण

ग्लिसरिन में मॉइश्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, गुलाबजल बढ़िया ऐस्ट्रिंजेंट है वहीं नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। इन तीनों को एक साथ मिलाकर कई दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। जो महिलाएं चेहरे पर केले का प्रयोग करती हैं उनकी स्किन लंबे समय तक यंग रहती है। केले में ऐंटी-एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं।

छोटी सी लौंग खाने से पूरे शरीर को मिलेगा फायदा

रोजाना खाना पकाने के लिए हम कई तरह के मसालों जैसे जीरा, दालचीनी, हल्दी आदि का उपयोग करते हैं। लौंग इन्हीं मसालों में से एक है, जिसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। खाने का स्वाद बढ़ाने वाली छोटी सी लौंग सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। बिरयानी का स्वाद बढ़ाने से लेकर चाय को कड़क बनाने तक के लिए लौंग का इस्तेमाल होता है। लौंग में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटैशियम, कैल्शियम आदि शामिल हैं।

ओरल हेल्थ के लिए गुणकारी

लौंग में एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो होरल हेल्थ के लिए जरूरी मानी जाती हैं। इसके सेवन से ब्लीडिंग गम, पाइरिया, दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन जैसी समस्याएं नहीं होती।

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है

लौंग में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। खासकर इसमें यूजेनॉल नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जो फ्री रेडिकल्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इससे शरीर को गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है।

पाचन दुरुस्त रखें

लौंग पाचन में मदद करने वाले एन्जाइम को बनाने मदद करती है, जिससे पाचन दुरुस्त रहता है और गैस, ब्लोटिंग, उल्टी आदि जैसी समस्याएं नहीं होती।

दर्द से राहत दिलाए

लौंग में यूजेनॉल नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो एक नेचुरल एनाल्जेसिक के तरह काम करता है। इसके सेवन से मांसपेशियों में दर्द, एठन, जकड़न जैसी समस्याएं नहीं होती।

कफ से राहत

लौंग में कफ नाशक गुण पाए जाते हैं, जो अस्थमा, खांसी जैसी श्वसन समस्याओं से राहत दिलाता है। लौंग के तेल का उपयोग करके खांसी से राहत पाई जा सकती है।

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाएं

लौंग में मैंगनीज और पोटैशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां दूर रहती हैं।

प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से से आश्विन मास की अमावस्या तक का समय श्राद्ध कर्म के रूप में जाना जाता है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन से श्राद्ध का आरंभ होगा। इस पितृपक्ष अवधि में पूर्वजों के लिए श्रद्धा पूर्वक किया गया दान तर्पण रूप में किया जाता है। पितृपक्ष पक्ष को महालय या कनागत भी कहा जाता है। हिंदू धर्म मान्यता अनुसार सूर्य के कन्याराशि में आने पर पितर परलोक से उतर कर कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अपने पुत्र - पौत्रों के यहां आते हैं।

पितृपक्ष का महत्व

पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, चंद्र की पाप ग्रहों जैसे राहु और केतु से युति को पितृ दोष के रूप में व्यक्त किया गया है। इस युति से मनुष्य जीवन भर केवल संघर्ष करता रहता है। मानसिक और भावनात्मक आघात जीवन पर्वत उसकी परीक्षा लेते रहते हैं। पितृ पक्ष में अधोलोखित मंत्रों से, या किसी एक मंत्र से काला तिल, चावल और कुशा मिश्रित जल से तर्पण देने से घोर पितृ दोष भी शांत हो जाता है।

1. ॐ पितृदोष शमनं हीं ॐ स्वधा
2. ॐ क्रीं कली सर्वपितृभ्यो स्वात्म सिद्धये ॐ फट!!
3. ॐ सर्वं पितृ प्रं प्रसन्नो भव ॐ!!
4. ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानम प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः अक्षन्न पितरो मीमदन्त पितरोतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्दध्वम ॐ पितृभ्यो नमः।

कौए को अर्पित भोजन

श्राद्ध पक्ष में कौओं को आमंत्रित कर उन्हें श्राद्ध का भोजन खिलाया जाता है। इसका एक कारण यह है कि हिन्दू पुराणों ने कौए को देवपुत्र माना है। एक कथा है कि, इन्द्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौए का रूप धारण किया था। त्रेता युग की घटना कुछ इस प्रकार है कि, जयंत ने कौए का रूप धर कर माता सीता को घायल कर दिया था। तब भगवान श्रीराम ने तिनके से ब्रह्मास्त्र चलाकर जयंत की आंख को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जयंत ने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी तब राम ने उसे यह वरदान दिया की, कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। बस तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चल पड़ी है।

श्राद्ध के महत्व के बारे में कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में वर्णन मिलता है। श्राद्ध का पितरों के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। पितरों को आहार और अपनी श्रद्धा पहुंचाने का एकमात्र साधन श्राद्ध है। मृतक के लिए श्रद्धा से किया गया तर्पण, पिण्ड तथा दान ही श्राद्ध कहा जाता है और जिस मृत व्यक्ति के एक वर्ष तक के सभी और्ध्व दैहिक क्रिया-कर्म सम्पन्न हो जाते हैं, उसी को "पितर" कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन व्यक्तियों का श्राद्ध मनाया जाता है, उनके नाम तथा गोत्र का उच्चारण करके मंत्रों द्वारा जो अन्न आदि उन्हें समर्पित किया जाता है, वह उन्हें विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। जैसे यदि मृतक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार देव योनि मिलती है तो श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को खिलाया गया भोजन उन्हें अमृत रूप में प्राप्त होता है। यदि पितर गन्धर्व लोक में हैं तो उन्हें भोजन की प्राप्ति भोग रूप में होती है। पशु योनि में हैं तो तृण रूप में, सर्प योनि में होने पर वायु रूप में, यक्ष रूप में होने पर पेय रूप में, दानव योनि में होने पर मांस रूप में, प्रेत योनि में होने पर रक्त रूप में तथा मनुष्य योनि होने पर अन्न के रूप में भोजन की प्राप्ति होती है।

श्राद्ध संस्कार

मृतक के लिए श्रद्धा से किया गया तर्पण, पिण्ड तथा दान ही श्राद्ध कहा जाता है और जिस मृत व्यक्ति के एक वर्ष तक के सभी और्ध्व दैहिक क्रिया-कर्म सम्पन्न हो जाते हैं, उसी को "पितर" को पितर कहा जाता है। वायु पुराण में लिखा है कि "मेरे पितर जो प्रेतरूप हैं, तिलयुक्त जौ के पिण्डों से वह तृप्त हों। साथ ही सृष्टि में हर वस्तु ब्रह्मा से लेकर तिनके तक, चाहे वह चर हो या अचर हो, मेरे द्वारा दिए जल से तृप्त हों। श्राद्ध के मूल में उपरोक्त श्लोक की भावना छिपी हुई है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने की परम्परा वैदिक काल के बाद से आरम्भ हुई थी। शास्त्रों में दी विधि द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा भाव से मंत्रों के साथ दी गई दान-दक्षिणा ही श्राद्ध कहलाता है। जो कार्य पितरों के लिए किया जाए वह "श्राद्ध" है।

अमावस्या का महत्व

पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि में श्राद्ध व दान का विशेष महत्व है। सूर्य की सहस्त्र किरणों में से अमा नामक किरण प्रमुख है जिस के तेज से सूर्य समस्त लोकों को प्रकाशित करता है। उसी अमावस्या में तिथि विशेष को चंद्र निवास करते हैं। इसी कारण से धर्म कार्यों में अमावस्या को विशेष महत्व दिया जाता है। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में सूर्यास्त तक घर के द्वार पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। पितृ पूजा करने से मनुष्य आयु,पुत्र, यश कीर्ति,पुष्टि, बल,सुख व धन धान्य प्राप्त करते है।

श्राद्ध का कारण

प्राचीन साहित्य के अनुसार सावन माह की पूर्णिमा से ही पितर पृथ्वी पर आ जाते हैं। वह नई आई कुशा की कोपलों पर विराजमान हो जाते हैं। श्राद्ध अथवा पितृ पक्ष में व्यक्ति जो भी पितरों के नाम से दान तथा भोजन कराते हैं अथवा उनके नाम से जो भी निकालते हैं, उसे पितर सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। ग्रंथों में तीन पीढ़ियों तक श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। पुराणों के अनुसार यमराज हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं। जिससे वह अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकते हैं। तीन पूर्वज पिता, दादा तथा परदादा को तीन देवताओं के समान माना जाता है। पिता को वसु के समान माना जाता है। रुद्र देवता को दादा के समान माना जाता है। आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता है। श्राद्ध के समय यही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह श्राद्ध के दिन श्राद्ध कराने वाले के शरीर में प्रवेश करते हैं अथवा ऐसा भी माना जाता है कि श्राद्ध के समय यह वहां मौजूद रहते हैं और नियमानुसार उचित तरीके से कराए गए श्राद्ध से तृप्त होकर वह अपने वंशजों को सपरिवार सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म में उच्चारित मंत्रों तथा आहुतियों को वह अपने साथ ले जाकर अन्य पितरों तक भी पहुंचाते हैं। श्राद्ध के हर कर्म में तिल की आवश्यकता होती है। श्राद्ध पक्ष में दान करने वाले को कुछ भी दान करते समय हाथ में काला तिल लेकर दान करना चाहिए। पितरों के निमित्त गुड़ एवं नमक का दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार नमक के दान से यम का भय दूर होता है। पितरों को धोती एवं दुपट्टा का दान करना उत्तम माना गया है। वस्त्र दान से यमदूतों का भय समाप्त हो जाता है। पितरों की प्रसन्नता हेतु इन चांदी, चावल, दूध वस्तुओं का दान किया जा सकता है।

पितृ पक्ष में क्या करें?

पूजा-पाठ के दौरान पितृ चालीसा का पाठ और पितृ मंत्रों का जप करना चाहिए।

ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें।

गरीब लोगों में श्रद्धा अनुसार अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए।

पितरों को भोजन अर्पित करना चाहिए।

पूजा के दौरान पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करें।

पशु-पक्षियों के लिए दाना डालना चाहिए।

पितृ पक्ष में रोजाना गीता का पाठ करना चाहिए।

तर्पण के दौरान कुश और काले तिल का इस्तेमाल करना चाहिए।

गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है।

पितृ पक्ष में क्या न करें?

पितृ पक्ष में लहसुन-प्याज का प्रयोग न करें। इसके अलावा मांस-मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही तांबे और पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

इसके अलावा बाल और दाढ़ी काटने की भी मनाही है।

किसी से भी लड़ाई झगड़ा न करें।

पितरों के लिए भोजन बनाते समय अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए।

ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन बनाना अशुभ माना जाता है।

पितृ पक्ष की अवधि पितरों को समर्पित है। इसलिए इस दौरान खरीदारी न करें।

साप्ताहिक समय माया

फ़ोन क्यों फटते हैं, और इसे अपने साथ होने से कैसे रोकें

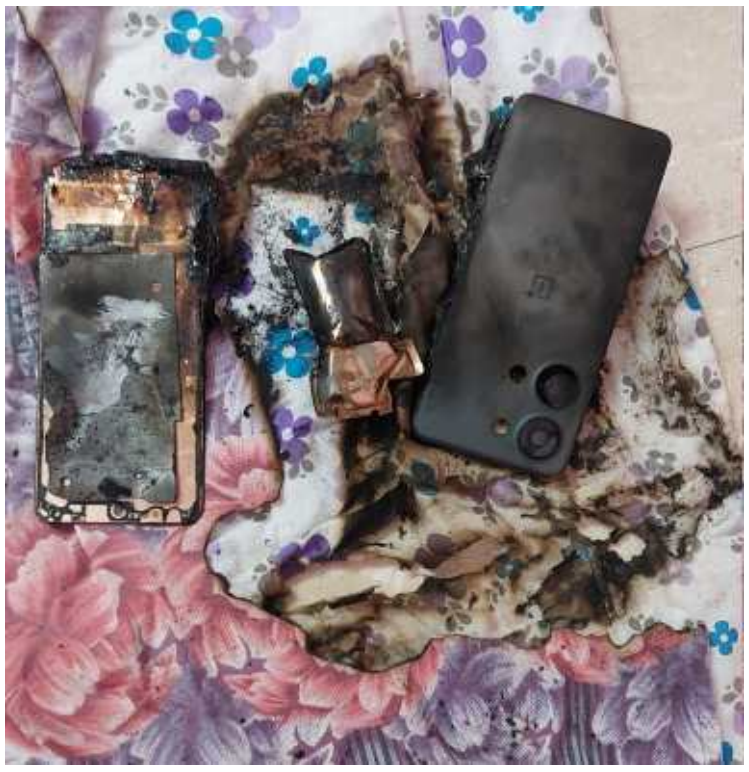

पेज 1 का शेष

आम तौर पर स्मार्टफ़ोन के फटने की संभावना नहीं होती, लेकिन ऐसा होता है। अगर खराब हार्डवेयर की वजह से ऐसा होता है, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सुझाव आपके फ़ोन को धुएँ में जाने से बचाने में मदद कर सकते हैं। कभी-कभी स्मार्टफ़ोन फट जाते हैं। पिछले साल ही, रात में चार्ज करते समय iPhone 4 में आग लग गई, भारत में एक बच्ची की मौत हो गई जब कथित तौर पर Redmi Note 5 Pro उसके चेहरे पर फट गया, और एयर इंडिया की फ्लाइट में एक व्यक्ति का फ़ोन फट गया, जिससे उसे आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। आपके स्मार्टफ़ोन के फटने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ऐसा होता है, जैसा कि कुछ साल पहले सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 की गड़बड़ी से पता चलता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और अगर कुछ है, तो आप इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं?

स्मार्टफ़ोन क्यों फटते हैं?

स्मार्टफ़ोन में आग लगने या फटने के कई कारण हो सकते हैं, और इसका लगभग हमेशा डिवाइस की बैटरी से संबंध होता है। आधुनिक मोबाइल डिवाइस लिथियम-आयन बैटरी द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें रिचार्ज करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक इलेक्ट्रोड का सावधानीपूर्वक संतुलन होता है। जब कुछ गलत होता है, तो बैटरी के आंतरिक घटक टूट सकते हैं और एक अस्थिर प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं जिससे आग लग सकती है।

यह कई कारणों से हो सकता है, लेकिन सबसे आम समस्या अत्यधिक गर्मी है। यदि चार्जिंग बैटरी या अधिक काम करने वाला प्रोसेसर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो यह फ़ोन के घटकों के रासायनिक मेकअप को बर्बाद कर सकता है। बैटरी के साथ, थर्मल रनवे नामक एक चेन रिएक्शन बैटरी को और भी अधिक गर्मी उत्पन्न करने और अंततः आग लगने या विस्फोट करने का कारण बनता है।

आपके फ़ोन के ज़्यादा गर्म होने का कारण अलग-अलग होगा। शारीरिक क्षति - गिरने या अत्यधिक झुकने से होने वाली क्षति - बैटरी के आंतरिक कामकाज को बाधित कर सकती है। फ़ोन को बहुत देर तक धूप में छोड़ना, मैलवेयर द्वारा CPU को ज़्यादा काम करना, या चार्जिंग में गड़बड़ी, ये सभी डिवाइस के भीतर शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं।

या यह आपके सीधे नियंत्रण से बाहर की कोई चीज़ हो सकती है। बैटरियाँ समय के साथ खराब होती जाती हैं, इसलिए यदि कोई डिवाइस कई सालों से इस्तेमाल की जा रही है - जैसे कि iPhone 4 जिसमें आग लग गई थी - तो आंतरिक घटकों का फीका पड़ना संभव है, जिससे सूजन और अधिक गर्मी हो सकती है। जैसा कि गैलेक्सी नोट 7 के मामले में हुआ था, फोन के उत्पादन में समस्या को दोषी ठहराया गया था, जिसका आप वास्तव में हिसाब नहीं लगा सकते।

चेतावनी संकेत

आपको चेतावनी नहीं मिल सकती है, लेकिन अगर आपको फ़ोन से फुफकारने या चटकने की आवाज़ आती है, या जलते हुए प्लास्टिक या रसायनों की गंध आती है, तो यह क्षतिग्रस्त हो सकता है और फटने के कगार पर हो सकता है। (स्पष्ट रूप से, इसके पास अपना चेहरा न रखें।) इसी तरह, डिवाइस से आने वाली अत्यधिक गर्मी पर ध्यान दें, खासकर चार्ज करते समय। अगर यह छूने पर बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो इसे तुरंत अनप्लग करें।

एक और बड़ा चेतावनी संकेत एक सूजी हुई बैटरी है, जो तब हो सकती है जब यह क्षतिग्रस्त हो गई हो या आंतरिक घटक खराब हो गए हों। डिवाइस के आकार में किसी भी तरह के बदलाव पर ध्यान दें, जिसमें एक उभरी हुई स्क्रीन, बड़ा सीम या फैला हुआ चेसिस शामिल है, जिसके कारण फ़ोन अब समतल सतह पर नहीं बैठ सकता है। हमने 2019 में उददुत सेवाओं के सभी निशान मिटाने की कोशिश करते हुए एक पुराने Android फ़ोन को लगभग उड़ा दिया। हमें अपनी परेशानी के लिए बस एक उभरी हुई बैटरी मिली।

अधिकांश आधुनिक स्मार्टफ़ोन अब आपको बैटरी निकालने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए यदि आप डिवाइस के बारे में चिंतित हैं, तो इसे बंद करें और तुरंत सर्विस के लिए ले जाएँ।

क्या आप अपने फोन को फटने से बचा सकते हैं?

जबकि आप अपने फोन की बैटरी पर पड़ने वाले तनाव को कम करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, लेकिन अगर समस्या निर्माण दोष की है तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। दोषपूर्ण घटकों के लिए बैटरियों का कठोर परीक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन सस्ते में बनी इकाइयों में ऐसी खामियाँ हो सकती हैं जो फोन को ज़्यादा गर्म कर सकती हैं।

नोट 7 के मामले में, डिज़ाइन दोष को दोषी ठहराया गया; इसे ठीक करने के लिए औसत उपभोक्ता कुछ नहीं कर सकता था। घटिया निर्माण की बात करें तो कोई त्वरित समाधान नहीं है। यही बात iPhone 4 के लिए भी लागू होती है; बैटरी समय के साथ स्वाभाविक रूप से खराब हो जाती है और अंततः उसे बदलने की आवश्यकता होगी, चाहे डिवाइस पर कितना भी ध्यान और देखभाल क्यों न दी जाए।

अपने फोन की बैटरी कैसे बचाएं

क्या आप चाहते हैं कि आपका फोन लंबे समय तक चले? आप हर समस्या को रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, जो आपके डिवाइस को स्वस्थ रखने और आग लगने से बचाने में मदद कर सकते हैं:

1. फ़ोन केस लें

हालांकि यह आम बात नहीं है, लेकिन फ़ोन गिरने से बैटरी खराब हो सकती है। PCMag के भूतपूर्व मोबाइल विश्लेषक स्टीवन विंकेलमैन से पूछें, जिन्हें समीक्षा के लिए मेल में एक चीनी निर्मित फ़ोन मिला था। हालाँकि, गलती से इसे रसोई के काउंटर से नीचे गिराने के बाद, फ़ोन से रासायनिक गंध निकली और कुछ ही मिनटों में आग लग गई।

हर डिवाइस गिरने के बाद आग नहीं पकड़ती, लेकिन इसके अंदरूनी हिस्से को सुरक्षित रखने का एक तरीका है इसे फ़ोन केस से ढकना - अधिमानतः फ़ोन के किनारे पर एक लिप वाला केस। ये केस पहले जितने महंगे नहीं हैं, और सबसे सस्ते केस भी कुछ न होने से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस समय, इसके बिना जाने का कोई बहाना नहीं है।

2. अत्यधिक तापमान से बचें

आप शायद जानते होंगे कि गर्मी आपके फोन का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ठंड के बारे में क्या? आपके फोन की बैटरी एक निश्चित तापमान सीमा में काम करने के लिए अनुकूलित है - 32-95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। बैटरी को नियमित रूप से कठोर परिस्थितियों में रखने से आंतरिक घटक फैलते और सिकुड़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंदर के हिस्सों को दीर्घकालिक नुकसान होता है।

अपराध का आरोप संपत्ति को विध्वंस करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

गुजरात के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनके एक परिजन के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज होने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने उनका घर गिराने की धमकी दी है. इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति के विध्वंस का आधार नहीं हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति के विध्वंस का आधार नहीं है और वह ऐसे विध्वंस की धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो ऐसे देश में अकल्पनीय हैं जहां कानून सर्वोच्च है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, 'ऐसे देश में जहां राज्य की कार्रवाइयां कानून के शासन द्वारा संचालित होती हैं, वहां परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया गया उल्लंघन परिवार के अन्य सदस्यों या उनके कानूनी रूप से निर्मित आवास के खिलाफ कार्रवाई को आमंत्रित नहीं कर सकता है. अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है. इसके अलावा कथित अपराध को न्यायालय में उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से साबित करना होता है. न्यायालय ऐसे विध्वंस की धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो ऐसे देश में अकल्पनीय हैं जहां कानून सर्वोच्च है. अन्यथा ऐसी कार्रवाइयों को देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है.' पीठ ने गुजरात के एक व्यक्ति की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह बात कही. व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के अधिकारियों ने एक सितंबर, 2024 को परिवार के एक सदस्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उसके घर को गिराने की धमकी दी है.

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस बीच, याचिकाकर्ता की संपत्ति के संबंध में सभी संबंधित पक्षों द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाएगी.

याचिकाकर्ता जावेद अली महबूबमिया सैयद की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल सैयद ने खेड़ा जिले के काठलाल गांव के राजस्व अभिलेखों का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित भूमि का सह-स्वामी बताया गया है.

उन्होंने कहा कि 21 अगस्त, 2004 के प्रस्ताव के माध्यम से कठलाल ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि पर आवासीय घर बनाने की अनुमति दी थी और याचिकाकर्ता के परिवार की तीन पीढ़ियां पिछले लगभग 2 दशकों से उक्त घरों में रह रही हैं.

उन्होंने कहा, 'फिर भी, जब 01.09.2024 को एक परिवार के सदस्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, तो नगर निगम के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के परिवार के घर को गिराने की धमकी दी है.'

वरिष्ठ वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 6 सितंबर, 2024 को खेड़ा जिले के नाडियाड के डिप्टी एसपी के पास भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 333 के तहत एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें स्थिति का वर्णन किया गया था और यह स्पष्ट किया गया था कि अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन नगर पालिका या नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोगों के पास याचिकाकर्ता के वैध रूप से निर्मित और वैध रूप से कब्जे वाले मकान/आवास को ध्वस्त करने के लिए धमकी देने या बुलडोजर का उपयोग करने जैसा कोई कदम उठाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए.

मालूम हो कि बीते 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा अपराध के आरोपी व्यक्तियों या यहां तक कि उनके परिजनों के घरों और निजी संपत्तियों को गिराने को सार्वजनिक प्रतिशोध की संभावित कार्रवाई बताते हुए सवाल उठाया था और कहा था कि कानून दोषियों के परिवारों के घरों को भी नष्ट करने की अनुमति नहीं देता.

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में कई राज्य सरकारों ने गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के घरों और संपत्तियों को ध्वस्त किया है.

सरकार की मंशा बिजली कंपनियों का निजीकरण, इसलिए नहीं कर रही नियमित लाइनमैनों की भर्ती

जबलपुर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की मंशा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के कंपनीकरण के समय प्रदेश की विद्युत कंपनियों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या 72000 थी। लेकिन नियमित अंतराल में नियमित पदों पर भर्ती नहीं किए जाने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों बहुत कम रह गई है। हालांकि ऊर्जा विभाग द्वारा बीच में बीच में संविदा और नियमित आधार पर जमीनी अधिकारियों की भर्ती की गई, लेकिन बिजली कंपनियों की लाइफलाइन लाइनमैनों की नियमित भर्ती की घोर अनदेखी की गई। बहुत जरूरी होने पर विद्युत वितरण कंपनियों में वर्ष 2013 में संविदा के आधार पर कुछ लाइनकर्मियो एवं परीक्षण सहायकों की भर्ती की गई, जो कि बढ़ती उपभोक्ताओं की संख्या के अनुपात में नाकाफी साबित हो रही है। हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 2000 से अब तक 24 वर्षों में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या चार गुना बढ़ चुकी है, इसलिए इसी अनुपात में नियमित कर्मचारियों की भी भर्ती की जानी चाहिए थी, लेकिन नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने से इन 24 वर्षों में सभी बिजली कंपनियों में नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या लगभग 12 प्रतिशत ही बची है। वहीं नियमित लाइन कर्मियों के विरुद्ध आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती की गई और आज हर कोई इससे वाकिफ है कि किस तरह आउटसोर्स कर्मियों का शोषण कर उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है।

हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 2000 से अब तक किसी भी सरकार और ऊर्जा विभाग द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ठोस नीति नहीं बनाई गई, जबकि विद्युत विभाग इतना अतिआवश्यक विभाग है कि इसके बिना आज आमजन के साथ उद्योग भी एक पल नहीं चल सकते। विद्युत विभाग एक ऐसा विभाग है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए विद्युत कंपनियों की नींव मजबूत करने के लिए नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती करना था, मगर सभी विद्युत वितरण कंपनियों में लगभग 50000 आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती कर विद्युत कंपनियों की नींव को कमजोर करने का कार्य किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार और ऊर्जा विभाग की मंशा बिजली कंपनियों का निजीकरण है।

संघ के केएन लोखंडे, एसके मौर्य, एसके सिंह, मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, अजय कश्यप, लखन सिंह राजपूत, अरुण मालवीय, इंद्रपाल सिंह, विनोद दास, संदीप दीपांकर, राहुल दुबे, दशरथ शर्मा, संदीप यादव, पवन यादव, अमीन अंसारी, पीएम मिश्रा, राकेश नामदेव आदि ने मध्य प्रदेश सरकार एवं ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि जिस अनुपात में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है, उस अनुपात में नियमित कर्मचारियों की पूर्ति के लिए सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन करते हुए नियमित कर्मचारियों की भर्ती की जाए और बिजली कंपनियों को निजीकरण की ओर न ले जाया जाए।

दिशाहीन हो चुका है मध्य वर्ग

भारतीयों का एक बड़ा वर्ग जो मूल्यों और नैतिकता की बात करते नहीं थकता, वह मौका पड़ने पर घोर अवसरवादी हो जाता है। सब नहीं, पर ज्यादातर लोग 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' की परंपरा के होते हैं। यह वर्ग मूल्यों और नैतिकता की बात तभी करता है, जब वह सेफ जोन में होता है।

वह तभी तक नैतिकतावादी होता है, जब तक उसके हित नहीं प्रभावित होते हैं। जैसे ही उसके हित प्रभावित होते हैं, वह मूल्यों से किनारा करने में देर नहीं लगाता। वह त्याग, तपस्या आदि गुणों को महापुरुषों के लिए ही आरक्षित मानता है। वह राम और भरत के सिंहासन-त्याग को लेकर खूब विह्वल होता है, लेकिन थोड़ी सी जमीन जायदाद को लेकर कहो अपने ही भाई के खिलाफ मुकदमा कर दे।

ऐसे लोग अतीत पर गर्व करो, पर वर्तमान को अपने हिसाब से जियो वाले होते हैं। उसकी राजनीतिक चेतना स्वतंत्र मूल्यों से नहीं, अपितु जाति और सांप्रदायिक सोच से निर्मित होती है। वह मनपसंद रंग का चश्मा पहनकर दुनिया को देखने की हसरत पाले हुए हैं। अपने पसंद के नेता की सौ बुराइयों को वह सह सकता है, पर रहेगा उसी के साथ। शुचिता को सुविधा के हिसाब से अपनाएगा।

भारत में अगर आज कोई घोर अवसरवादी वर्ग है, तो वह है मध्य वर्ग। वही वर्ग जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महती भूमिका निभाई थी। दुर्भाग्य से आज वही दिशाहीन है। इसने अपने राष्ट्रनायकों के साथ सर्वाधिक विश्वासघात किया है। फिर चाहे वो भगत सिंह हों, सुभाषचंद्र बोस हों, आजाद हों या स्वामी विवेकानंद। इन सभी नायकों की फोटो को इस्तेमाल करना और उन्हें अपने घर, दफ्तर की सजावट की वस्तु बना देना इसी मध्य वर्ग का कौशल है। पर वह शिक्षा इनसे भूले से भी नहीं लेता। बातें आदर्शवाद की करेगा और आचरण बिलकुल उसके विपरीत।

वह कबीर को प्रायः ही उद्धृत करता है, पर अन्य नायकों की तरह इन्हें भी जीवन में उतारने से सहज परहेज करता है। वह भगत सिंह और सुभाष बाबू को याद तो करेगा, भावुक श्रद्धांजलि भी देगा, पर उनके विचारों पर चर्चा नहीं करेगा। वह उनके साहस की बढ़-चढ़ कर प्रशंसा करेगा, लेकिन उनकी शिक्षाओं को दरकिनार कर प्रेरणा सांप्रदायिक तत्त्वों से लेगा। यह अपने अतीत को पढ़ना भूल चुका है। पढ़ने का काम वह अपने नेतृत्वकर्ताओं को सौंप चुका है, लिहाजा वह सूचनाओं से भी कट चुका है। इसका फायदा उसके हित के नाम पर राजनीतिक नेतृत्व उठाता है। घोर आत्मकेंद्रीकता के चलते वह सर्वसमाज के मूल्यों से कट चुका है। वह लामबंदी के गुर सीख रहा है।

वह इतिहास को पढ़ना नहीं चाहता, वह सिर्फ पार्टी के आईटी सेल के फॉर्वर्डेड मैसेज पढ़ता है और उसको ही आगे बढ़ाता है। वह अपने स्वतंत्रता आंदोलन के उन नायकों के प्रति अनैतिकता की हद तक निष्ठुर हो चुका है, जिन्होंने सबको साथ लेकर चलने की शिक्षा दी है। वह सांप्रदायिक शक्तियों की कठपुतली बन चुका है। उच्च वर्ग तो वैसे भी अपनी जड़ों से कटा हुआ भौतिकतावादी है। आशा मध्य वर्ग से थी, लेकिन उसकी हालत आज सर्वाधिक खराब है।

वह स्थापित विचारधारा पर तर्क-वितर्क नहीं करता और विचारधारा से भी ज्यादा वह विचारधारा के घोषित नायक के प्रति समर्पित हो, उसका अंधानुयायी हो जाता है, भले ही उस नेतृत्व का आचरण विचारधारा के स्थापित मानकों के खिलाफ हो।

अगर यहां एक बार किसी का नायकत्व स्वीकार कर लिया गया, फिर उसके आचरण पर सवाल खड़े करने अधिकार किसी को नहीं होता। यह मानसिक दासता है। चालाक नेतृत्व ने सांप्रदायिक चौहद्दी में रच-बस गए मध्य और निम्न मध्य वर्ग को अन्य धर्मों के कल्पित भय दिखाकर एकजुट कर दिया है। ऐसे में ध्रुवीकृत समुदाय एक ठोस वोटबैंक में तब्दील हो, सत्ता प्राप्ति में सहायक बनता है। इसीलिए राजनीतिक नेतृत्व नए-नए तरीकों से ध्रुवीकरण को यथावत रखना चाहता है। सजातीयता और सांप्रदायिकता इसमें सहायक होती है। हम इतने संकीर्ण हो जाते हैं कि हम नेतृत्व के अनैतिक कामों को भी नजर अंदाज करते हैं और नेतृत्व को तो यही चाहिए ही। यह प्रवृत्ति नागरिकों को मानव भेड़ों रूपांतरित कर देती है। यही कारण था कि जब आडवाणी, जोशी और सिन्हा को किनारे किया गया तो प्रतिरोध के स्वर कहीं से न सुनाई दिए। यही कारण था कि किसान कानूनों के स्थापित प्रक्रियाओं से इतर पास करने के तरीके पर समर्थकों की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। क्योंकि प्रतिबद्धता पार्टी नेतृत्व के प्रति थी न कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति।

यही कारण था कि प्राण प्रतिष्ठा का समय भगवान राम के जन्म के पहले निर्धारित करने, उसे इवेंट में तब्दील करने और चारों शंकराचार्यों की अनुपस्थिति को लेकर किसी को अफसोस नहीं हुआ। उल्टे शंकराचार्य ही निशाने पर लिए गए। हम बस निर्देशों का यंत्रवत अनुपालन करने वाले बनकर रह जाते हैं।

हम सवाल नहीं करते उल्टे सवाल करने वालों पर सवाल करते हैं। हम विधायकों की अनगिनत पेंशनों पर सवाल नहीं कर पाते। लोग बड़ी अर्थव्यवस्था का गाना गाते हैं, लेकिन बेरोजगारी पर नहीं बोलते, वे भारत पर बढ़ते कर्ज की चिंता नहीं करते। वे वैश्विक डंका की बात करते हैं, पर मणिपुर पर मुंह नहीं खोलते।

क्या पीएम केयर फंड का हिसाब न दिये जाने पर कहीं कोई असंतोष दिखा? नहीं न!

ऐसी स्थिति हर पार्टी के अंधानुयाइयों की होती है। ऐसे में हम मूल्यों के नहीं, बल्कि व्यक्ति के उपासक हो जाते हैं, अपनी वैचारिक सत्ता को गिरवी रखकर। दुष्यंत जी का यह शेर बड़ा मौजूं हैः

'रहनुमाओं की अदाओं पर फ़िदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो'

देश में 125 करोड़ की आबादी पर 25 करोड़ भी दुधारू पशु नहीं

पेज 1 का शेष

विधानसभा मेंस्वास्थ्य मंत्री ने सन 2006 में स्वीकार किया था कि 1984 से सांची और अमूल के नमूने नहीं लिए गए, आखिर क्यों जबकि दूसरी ओर अकेले इंदौर में ही घोर भ्रष्ट खाद्य सुरक्षा व पंजीयन अधिकारी मनीष स्वामी जो पूर्व में भी 6-7 साल तक इंदौर में रहा और पुनः मोटा धन देकर इंदौर में बैठ अपने कार्यक्षेत्र के अधिकांश दुग्ध विक्रेताओं मिठाई नमकीन वालों से लेकर व्यापारियों से मोटा महीना वसूल रहा है। यही हाल खाद्य सुरक्षा एवं पंजीयन अधिकारी धर्मेंद्र सोनी, और मनोज रघुवंशी का भी है के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरज श्रीवास्तव प्रभु लाल डोडियार राकेश प्रसाद त्रिपाठी, कु.अलमेलु पीव्ही, अवधेश अग्रवाल का भी है। जो छोटे व्यापारियों को घेर कर उनके नमूने लेकर पास फेल करवाने का खेल करके भी मोटी वसूली भी करते रहते हैं। यही हाल इंदौर संभाग के इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, उज्जैन संभाग के आगर मालवा, देवास, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम के साथ पूरे प्रदेश और देश का भी है। जहां सालों से घोर भ्रष्ट जालसाज खाद्य अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक मोटा धन वसूल व बांटकर एक ही स्थान पर वर्षों से कुंडली मारे बैठकर छोटे उद्योगी व्यापारियों दुकानों को खत्म करने के लिए मोटी वसूली करने के बाद में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटे फायदे के लिए षड्यंत्र करते रहते हैं। जब देश की 125 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ भी दुधारू पशु नहीं तो देश की आबादी को 70 करोड़ लीटर प्रति व्यक्ति आधा लीटर दूध जिसमें बच्चों से बुजुर्गों तक पीने चाय कॉफी आदि में उससे बने 2000 टन घी, मक्खन, दही, छाछ, मिठाइयो चाकलेट आदि में कौन सा दूध उपयोग किया जा रहा है। जबकि देश का वाचाल घोर लालची मूढ़ मोदी जिसके प्रधानमंत्री पद पर बैठकर दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत में खुलकर गोमांस खाने के लिये व्यवस्था करवाने के साथभारत विश्व का पहला नंबर का को मांस निर्यातक भी है। जिसमें प्रतिदिन 20 लाख से ज्यादा गायों को काट दिया जाता है। दूसरी तरफ जिन गायों का किसान पालन पोषण करते थे उनके पैदा किए हुए नर बछड़े बड़े होकर खेती में हल चलाने सामान ढोने पानी निकालने काम करते थे। कृषि में ट्रैक्टर, जलपंप आने से बच्चों का उपयोग खेती में पूरी तरीके से खत्म हो जाने के कारण अब किस भी गए नहीं पाते हैं और जो पलते हैं उनका दूध निकाल कर छोड़ दिया जाता है अमूल और सांची जैसी हर राज्य की अपनी दुग्ध संस्थाएं जो करोड़ों लीटर दूध बेचती है।

वे स्वंय दूध का परीक्षण नहीं करते और इसीलिए वे सभी मोटा लाभ कमाने जानबूझकर घातक रासायनिक व कुछ प्रतिशत तक विदेश से आयातित दूध पाउडर का दूध बनाकर बेंच रही हैं। आखिर ये जालसाज हर दिन मध्य प्रदेश में ही हर जिले में बेंचे जा रहे सभी प्रकार के दूध व उसके अन्य उत्पादों छाछ मक्खन दही घी मिठाइयां मीठा दूध चॉकलेट के नमूने क्यों नहीं ले उनके परिणामों को सार्वजनिक करती जबकि लगभग 2 करोड़ व्यक्ति सांची और अमूल के दूध का उपयोग करते हैं।बस छोटे-छोटे व्यापारियों विक्रेताओं को डराने-धमकाने उनके लाइसेंस रद्द करने की और नियम विरुद्ध दुकानें तोड़ने सील करके डराने धमकाने का सलंग्री ही क्यों करती रहती है जिसमें प्रशासन के भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी जो एसडिएम एडीएम और डीएम के पद पर बैठे हुए हैं। वसूली में हिस्सा मार अपनी वाहवाही करवाने समाचार पत्र प्रकाशित करवाते हैं।

साप्ताहिक समय माया

देश में 125 करोड़ की आबादी पर 25 करोड़ भी दुधारू पशु नहीं

80% दूध व उसके उत्पाद सब घातक रसायनों के

आखिर अमूल, सांची व सभी राज्यों की सहकारिता के दूग्ध उत्पादों की जांच क्यों नहीं करते महीना वसूली विशेषज्ञ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, छोटों को बड़ों के लिए खत्म करने पर तुले रह उन्हीं के नमूने और जुर्माना करवाते हैं।

अमेरिकी औषधि एवं खाद्य उत्पादकों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के धन से चलने वाली षड्यंत्रकारी संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाम विश्व घातक संगठन व बहुराष्ट्रीय कंपनी के इसारे पर थोपे गए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 06 जिसमें अकेले वॉलमार्ट ने हीं 37500 करोड डॉलर अर्थात साडे 33 लाख करोड़ रु भारत सरकार की संसद को बांट कर यह कानून बनवाया था। भारत के देशी टाटा बिरला अंबानी मित्तल व अन्य के साथ विदेशी स्वामित्व वाली आईटीसी युनिलीवर कैडबरी पार्ले जैसी अनेकों कंपनियों ने मिलकर भी सन 2002 से ही मोटा पैसा जो लगभग 20 लाख करोड़ था बांटकर अटल बिहारी की सरकार से ही उस वक्त अंबानी ने अपने रिलायंस रिटेल के नाम से शॉपिंग मॉल के साडे 500 आउटलेट्स खोल दिए थे। तब से ही उस खाद्य सुरक्षा के नाम पर सारे देश के किसने से सीधा ओने-पोने माल खरीद, उसकी पैकेजिंग कर अपनी मनमानी कीमत पर बेचने के लिए खाद्य पदार्थों पर कब्जा करने और प्रतियोगियों 10 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारियों उद्योगों दुकानों विक्रेताओं मंडियों को खत्म करने कानून को बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। जिसे 1000 करोड़ पर सांसदों को बांट बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अपने हितों को साधने उनके बनाये हुए कानून को मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 में बनाकर थोप दिया था। परंतु समय माया समाचार पत्र ने अक्टूबर 2006 में अकेले ही उस कानून के षड़यंत्रों की सच्चाई बता और एक करोड़ से ज्यादा दुकानदारों उद्योगों बाजारो मंडियों खत्म करने के षड़यंत्र से 10 करोड लोगों के बेरोजगार करने का सच बता कर देश पर लागू होने से 5 साल तक रोके रखा। परंतु अन्ना के फर्जी भ्रष्टाचार खत्म करने के भाजपा

प्रायोजित जुलाई 2010 के आंदोलन में 23 जुलाई को यह घोषणा करना की अभी है आंदोलन 15 अगस्त के बाद करूंगा सरकार ने कुछ संशोधनों के बाद 5 अगस्त 2010 से इसे देश पर लागू कर दिया। इसमें केंद्रीय व राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बना दिया गया। परंतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के षड्यंत्र के अंतर्गत यहां पर भी 20 करोड रुपए प्रतिदिन से ज्यादा की बड़ी-बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को केंद्र के अंतर्गत रखने के बाद जिसमें अधिकांश बड़ी देसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनके अधिकारी दिल्ली में बैठते हैं और वहीं के खाद्य प्रशासन के मुख्य खाद्य प्रशासक को मोटा और बहू रुपए में महीना देते हैं सारे कारोबार कानियंत्रण उनके हाथ में दिया गया ताकि उनके इसारे पर नाच कर उनके खाते में सुरक्षा अधिकारी उनके सभी घातक रसायन युक्त खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों को धन के बदले आंख मींचकर श्रेष्ठता और सुरक्षा का प्रमाण पत्र दे जनता को भ्रमित कर उन खाद्य पदार्थों को सेवन करने के लिए विवश कर सकें। जबकि छोटी इकाइयों को राज्यों के जिलों के उपसंचालक सह मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के नियंत्रण में रखने के साथजिलों में भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन में खाद्य के लिए अलग से अभिहित अधिकारी की नियुक्ति करने की व्यवस्था कर दी गई। जो अधिकांश जिलों में अभी तक नहीं है। हर जिले मेंवरिष्ठ और कनिष्ठ खाद्य निरीक्षकों की घोषणा और गजट नोटिफिकेशन के बाद उन्हें अनेकों अधिकार दे दिए गए। इसके साथ ही उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के ज्ञान अनुभव वरिष्ठता के आधार पर संभागीय स्तर पर उनका एक उड़न दस्ता भी बना दिया गया। साथ में विश्व घातक संगठन ने पूरे देश में लगभग 5000 से ज्यादा चलित खाद्य पदार्थों की जांच प्रयोगशाला के लिए वाहनो को केंद्र सरकार के माध्यम से भी उपलब्ध करवाये।

जो अधिकांश समय वर्तमान में हर संभाग में खड़े रहते हैं उनका उद्देश्य यही था कि वह गांव से लेकर शहरों तक उन पर रोक सालों के माध्यम से छोटे व्यापारियों उद्योगों दुकानदारों को जाट के नाम पर डरती धमकाती रहे और उसकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने लेने के नाम पर मोती वसूली करते रहें इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ एटीएम एसडीएम को भी असीमित वसूली के अधिकार दिए गए। जिसका सच जानने के लिए प्रदेश केसभी जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अधिकृत मोबाइल नंबरों के अतिरिक्त उनके जो निजी मोबाइल नंबर भी हैं। उनकी केवल पिछले 1 साल की कॉल रिकॉर्डिंग देखी जाए तो हर बंदा करोड़ों रुपए वसूल कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एडीएम, एसडीएम, कलेक्टर के साथ भोपाल स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासक और स्वास्थ्य व मुख्यमंत्री तक को करोड़ों रुपए पहुंचा रहा है। प्रदेश में कार्यरत दो एक गुजराती अमूल और दूसरी मध्य प्रदेश की सहकारिता में चल रही दुग्ध सहकारी संघ जो दूध वह उसके अन्य उत्पाद यथा 3 से 5 प्रकार के दूध मीठा दूध घी मक्खन छाछ, दही, पेडे जनता को बेच रहे हैं। (शेष पेज 7 पर)

रेलवे को हड़पने और जनता को लूटने सारे षड्यंत्र, हटाई सामान्य बोगियां

स्टेशन पर चाय बेचने वाला हड़प व बर्बाद कर रहा रेल्वे

शायद इस बार लक्ष्य गरीबों से उनकी यात्रा का सुख-चैन छीनना है। कांग्रेस शासनकाल में जिस रेल को भारत में सबसे सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए वरदान माना जाता था, नरेन्द्र मोदी सरकार की खोखली और गलत नीतिओं से वही रेल यात्रा अब यात्रियों के लिए अभिशाप बन चुकी है।

आइये ! रेल की बर्बादी को समझते हैं-

रेल दुर्घटना अब आम बात हो चुकी है। वर्ष 2023-24 में ही रेल दुर्घटनाओं में 313 यात्रियों और 4 रेल कर्मियों की मौत हुई है। वहीं वर्ष 2023-24 में रेल दुर्घटनाओं में 744 यात्री और 5 रेलकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रेल बोर्ड ने स्वयं स्वीकार किया है कि कर्मचारियों की कमी के कारण लोको पायलटों को ज्यादा समय तक काम करना पड़ता है जो दुर्घटनाओं की मुख्या वजह है।

राज्यसभा में लिखित जवाब में रेल मंत्री ने स्वयं बताया है कि रेलवे के सभी जोन में ग्रुप सी पोस्ट में 2,48,895 पद खाली हैं जबकि ग्रुप ए और बी पदों में 2070 पद खाली हैं।

(शेष पेज 3 पर)

इंजन डब्बे ट्रैक इलेक्ट्रिक लाइनें संचार व्यवस्था स्टेशन आदि के रखरखाव व निर्माण के 10% ज्यादा कीमत पर ठेके, फिर भी बर्बाद, भर्तीयां नहीं, बुकिंग दलालों के चंगुल में

जनता को लूटने डकैकी डालने के लिए और पूरी पैसेंजर ट्रेनों से जो करोड़ों लोग यात्रा करके अपने गन्तव्य तक पहुंच कर अपनी रोजीरोटी चलाते थे। जैसा कि षड्यंत्र कर पूरे देश की सारी ट्रेनों से सभी अनारक्षित बोगीज को हटा दिया गया। उसके बदले में 10 गुना ज्यादा किराए परअब बंदे भारत ट्रेन चलाकर आम गरीब आदमी से जो गरीबों की यात्रा का सस्ती सुलभ सरल माध्यम हुआ करती थी। मोदी ने आने के बाद उसको खत्म करने का शुरू कर दिया था जो अब अपने मुकाम पर पहुंचाया जा रहा है। मोदी सरकार ने भारतीय रेल को बर्बाद कर दिया, अब हर यात्रा में अंतिम यात्रा सा खौफ है।

वैसे तो नरेन्द्र मोदी और BJP को देश बर्बाद करने के लिए हमेशा याद किया जायेगा, परन्तु रेल की बर्बादी में मोदी सरकार ने कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाई है।

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com

करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत

साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व samaymaya.com की वेबसाइट पर समाचार, शिकायतें और विज्ञापन (प्रिंट एवं वीडियो) के लिए संपर्क करें

मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है एवं संवाददाता नियुक्त करना है

मो. 9425125569 / 9479535569

ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958